कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई)

जनवरी, 2020 माह का मासिक सारांश

जनवरी, 2020 माह के महत्वपूर्ण कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं:

(क) श्री अमित शाह, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार ने माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री, श्री रतन टाटा, अध्यक्ष टाटा ट्रस्ट और गुजरात सरकार तथा एमएसडीई के अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में 15.01.2020 को, गांधीनगर में भारतीय कौशल संस्थान (आईआईएस) की आधारशिला रखी।

(ख) माननीय विदेश मंत्री, श्रीलंका सरकार ने कौशल क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए 09.01.2020 को माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री को बुलाया। चर्चा के आधार पर, कौशल क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन करने पर विचार चल रहा है।

(ग) प्रधान मंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम (पीपी) में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को शामिल करने के संबंध में सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में 21.01.2020 को एक बैठक आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के लिए स्कीम से 15% भौतिक लक्ष्य और इतने ही वित्तीय परिव्यय के आवंटन का प्रावधान है। पीएम 15 वी के साथ पीएमकेवीवाई का अभिसरण चल रहा है।

(घ) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) टीम के साथ 13.01.2020 को पीएमकेवीवाई स्कीम के अंतर्गत अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं, कार्यान्वयन के तरीकों, प्रशिक्षण तकनीकों आदि पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी।

(ङ) आजीविका हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) कार्यक्रम के तहत प्रगति:

i. महात्मा गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमजीएनएफ) कार्यक्रम के तहत अध्येताओं को सूचीबद्ध करने के लिए 15.01.2020 को साक्षात्कार पूरा हुआ और एमजीएनएफ के कार्यान्वयन के लिए एमएसडीई के शैक्षणिक भागीदार आईआईएम बैंगलोर द्वारा 75 अध्येताओं को सूचीबद्ध किया गया है।

ii. क्षमता निर्माण और जिला योजना पर परामर्शी कार्यशालाएं आयोजित की गईं: रायपुर (छत्तीसगढ़)- राज्य कौशल विकास मिशन (एसएसडीएम) और जिला कौशल समिति (डीएससी) के सदस्यों के साथ-साथ सभी जिलों के अधिकारियों के लिए 08.01.2020

को जिला कौशल योजना पर कार्यशाला। छत्तीसगढ़ और लखनऊ (उत्तर प्रदेश)- उत्तर प्रदेश के 51 जिलों के लिए 23.01.2020 को जिला कौशल योजना पर कार्यशाला हुई।

iii. संकल्प के कार्यान्वयन के लिए 3 राज्यों, अर्थात् गोवा (1.02 करोड़ रुपए), मिजोरम (1.81 करोड़ रुपए) और सिक्किम (1.98 करोड़ रुपए) के रूप में कुल 4.81 करोड़ रुपए जारी किए गए।

(च) <u>औद्योगिक मूल्य संवर्धन (स्ट्राइव) के लिए कौशल सुदृढीकरण के तहत प्रगति:</u>

i. छह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) ने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब तक कुल 211 आईटीआई ने प्रदर्शन आधारित अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

ii. 116 अधिकारियों को राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) अनुपालन प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षित किया गया है। अब तक 13,510 अधिकारियों को एनएसक्यूएफ के तहत प्रशिक्षित किया जा चुका है।

iii. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के शिल्प अनुदेशकों/प्रशिक्षकों के लिए भर्ती, प्रशिक्षण और कैरियर प्रगति नीति दस्तावेज को सार्वजनिक डोमेन में फीडबैक के लिए रखा गया है।

iv. उद्योग शिक्षुता पहल (आईएआई) योजना के कार्यान्वयन में उनका समर्थन करने के लिए स्ट्राइव परियोजना के तहत चयनित उद्योग समूहों के लिए वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया।

v. स्ट्राइव परियोजना के लिए पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू करने के लिए विश्व बैंक टीम (21-22 जनवरी) के साथ बैठकें हुईं।

vi. हरियाणा राज्य में पायलट प्रायोगिक अध्ययन आयोजित करने के लिए प्रश्नावली को अंतिम रूप देने के लिए 28.01.2020 को हरियाणा सरकार और व्हीबॉक्स के साथ बैठक हुई।

vii. चरण-2 के तहत ग्रेडिंग के लिए 2,693 आईटीआई का बाहरी एजेंसी द्वारा भौतिक रूप से दौरा किया गया। अब तक 11,293 आईटीआई की जांच बाहरी एजेंसी द्वारा भौतिक रूप से की गई है। ग्रेडिंग पर शिकायत निवारण समिति दो बार (6-9 जनवरी, 20-22 जनवरी) बैठक कर चुकी है और कोर ग्रेडिंग कमेटी में डालने के लिए 3000 आईटीआई के मामलों को निपटाने के लिए शिकायतों का निपटारा किया गया।

****